साप्ताहिक
जागत गांव हमार
पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक
RNI-MPHIN/2015/72544
चौपाल से भोपाल तक
भोपाल, सोमवार, 30 सितंबर-06 अक्टूबर 2024 वर्ष-10, अंक-24
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

-मप्र में रबी सीजन में भी शुरू हो गई खाद की मारामारी, कृषि मंत्री के गृह संभाग में भी कमी गंभीर, किसान परेशान

-किसानों को सीमित मात्रा में खाद का किया जा रहा वितरण
-विंध्य अंचल में बोवनी देरी से होती है, इसलिए वहां मांग कम

खाद की किल्लत! आठ लाख टन डीएपी की मांग, मिला सिर्फ 1.20 लाख टन

भोपाल। जागत गांव हमार

रबी सीजन प्रारंभ ही हुआ है और खाद के लिए मारामारी अभी से शुरू हो गई है। कई जगहों पर खाद दुकानों के बाहर लाइनें लगने लगी हैं तो कुछ जगह रतजगा हो रहा है। बोवनी के लिए सर्वाधिक मांग डीएपी की होती है। इसका ही संकट है। मप्र ही नहीं, पूरे देश में किल्लत की स्थिति है। केंद्र सरकार से मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही है। नतीजतन, पूरे सीजन के लिए आठ लाख मीट्रिक टन डीएपी की मांग की गई, लेकिन अब तक एक लाख 20 हजार टन की ही उपलब्धता हो सकी है। ग्वालियर-चंबल अंचल में खाद को लेकर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना के जिले मुरैना में सबसे ज्यादा मारामारी है। यहां डीएपी खाद की मांग 24,500 मीट्रिक टन है जबकि सरकार ने अब तक मात्र 8,247 मीट्रिक टन ही उपलब्ध कराया है। ऐसे में जिस किसान को 10 बोरी की जरूरत है, उसे दो बोरी दी जा रही है। तीन दिन कतार में लगने के बाद किसान को टोकन और फिर खाद मिल पा रही है। दरअसल, ग्वालियर-चंबल अंचल में सबसे पहले रबी फसलों की बोवनी होती है। इसी तरह, मालवा-निमाड़ अंचल में सोयाबीन फसल की कटाई के साथ ही किसानों ने रबी फसलों के लिए एनपीके खाद का इंतजाम करना शुरू कर दिया है।

देवास जिले में कई स्थानों पर सोसायटी में या तो खाद वितरण अभी चालू नहीं हुआ है या फिर सीमित मात्रा में मिल रहा है। ऐसे में, बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय में अनाज मंडी के सामने स्थित एमपी स्टेट एग्रो के गोदाम में पहुंच रहे हैं। यहां पर पावती और आधार कार्ड कतार में रखकर नंबर लगाए जा रहे हैं। धार जिले के राजगढ़ क्षेत्र में कंजरोटा मार्ग स्थित विपणन संघ के भंडारण केंद्र पर नकद में यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की भीड़ लग रही है। विंध्य-महाकोशल अंचल में बोवनी अक्टूबर के अंत में होती है, इसलिए यहां मांग कम है।

डीएपी की स्थिति

- अभी तक 70 प्रतिशत खाद की आपूर्ति करती हैं सहकारी संस्थाएं
- मध्य प्रदेश में 4,500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति
- 280 विपणन संघ के डबल लाक और विक्रय केंद्रों से खाद का विक्रय
- तीन लाख मी.टन डीपीए के भंडारण का लक्ष्य था, 98 हजार टन ही मिला
- 143 मीट्रिक काम्प्लेक्स खाद की व्यवस्था की गई कमी को पूरा करने के लिए

इसलिए गड़बड़ाई व्यवस्था

खरीफ सीजन-2023 की तुलना में इस वर्ष डीएपी का 3.51 लाख मीट्रिक टन कम भंडारण हुआ। इसकी पूर्ति के लिए एनपीके का 2.44 लाख मीट्रिक टन अधिक भंडारण किया गया। सभी जिलों को निर्देश दिए गए कि काम्प्लेक्स का भंडारण करें।

सहकारिता विभाग| अधिकारियों का कहना है कि किसानों की मांग डीएपी की है, जो कम है। काम्प्लेक्स और एनपीके भी वही काम करता है। इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। केंद्र से खाद की आपूर्ति को लेकर लगातार पत्राचार हो रहा है।

कृषि विभाग| अधिकारियों का कहना है कि ग्वालियर-चंबल अंचल में पहले बोवनी होती है, इसलिए रैक मवमेंट वहीं रखा है। वहीं, खाद को लेकर अफरातफरी न मचे इसके लिए कलेक्टर अपने-अपने स्तर पर व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं।

भिंड कलेक्टर का नवाचार| संजीव श्रीवास्तव ने व्यवस्था बनाई है कि जिले में केंद्रों पर उपलब्ध उर्वरक स्टाक सूची में विक्रेता के मोबाइल नंबर और नाम के मैसेज किसानों तक पहुंचाएं।

किसान रासायनिक खाद का उपयोग कम करें, इसलिए स्टाक में कटौती की गई है। मार्कफेड, अपेक्स बैंक, कृषि और सहकारिता विभाग के अधिकारी प्रतिदिन बैठक करके जिलों में खाद की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। ग्वालियर, गुना, शिवपुरी और अशोकनगर में सहकारी समितियों को स्थिति को देखते हुए नकद विक्रय की सुविधा दी गई है। मार्कफेड ने विक्रय केंद्र बढ़ाने के निर्देश प्रबंधकों को दिए हैं।

पीसी पटेल, उप संचालक, कृषि विभाग, मुरैना

सीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान कहा

खाद-बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी

इंदौर, सीएम डॉ. मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में खाद-बीज की उपलब्धता और वितरण की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में खाद-बीज की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं होगी। सीएम ने निर्देश दिए कि जो कालाबाजारी करते पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। रबी सीजन में किसानों को खाद-बीज की कमी नहीं रहे। इसके लिए अभी से ही खाद-बीज के भंडारण और आपूर्ति करने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर कृषि विकास अधिकारियों को 15 अक्टूबर तक प्रशिक्षण दिया जाए। प्रदेश में फसलों के बोने के क्षेत्र चिन्हित कर खाद-बीज की व्यवस्था करें। अक्टूबर-नवम्बर माह में खाद-बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे, जिससे किसानों को कोई असुविधा न हो। जन-प्रतिनिधियों एवं जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाद-बीज की उपलब्धता के संबंध में चर्चा की जाएगी।

डीएपी का आवंटन बढ़ा

बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार ने डीएपी का आवंटन बढाकर 8 लाख मीट्रिक टन कर दिया है, जबकि रबी 2024-25 के लिए 6 लाख मीट्रिक टन डीएपी के आवंटन की सहमति दी गई थी। डीएपी के स्थान पर एनपीके के उपयोग के लिए जिलों को निर्देश जारी किए गए, जिससे खरीफ 2024 में डीएपी की कमी परिलक्षित नहीं हुई। डीएपी की कमी की पूर्ति के लिए प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में यूरिया एवं एसएसपी उपलब्ध है।

-दिग्विजय सिंह ने कहा

खाद की हो रही कालाबाजारी

इंदौर, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर मध्यप्रदेश में खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। कहा कि कालाबाजारी में शासन प्रशासन की हिस्सेदारी है। दिग्विजय ने सरकार से मांग की है कि सहकारिता और विपणन संघ के माध्यम से खाद का वितरण हो। निजी क्षेत्र से खाद के विपणन में जमकर धांधली हो रही है। कालाबाजारी पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम है। फर्टिलाइजर को लेकर प्रदेश को हर साल 8 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ 15 फीसदी मांग ही पूरी हो पाती है। प्रदेश के हर गांव के पास सरकारी गोदाम है। ईमानदारी से सरकार फर्ज निभाएं और व्यवस्था में परिवर्तन करें। कहा कि- प्रदेश का किसान परेशान है। सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए।

पशु संगणना में भारत विश्व में प्रथमः तैयारियों के संबंध में राज्य स्तरीय कार्यशाला एवं प्रशिक्षण

21वीं पशु संगणना में पूरी तरह ऑनलाइन होगा डाटा कलेक्शन

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। पशु संगणना में जहां भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, वहीं विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भी भारत में ही होता है। विश्व के सकल दुग्ध उत्पादन का 25 फीसदी भारत में होता है। भारत में कृषि उत्पादन में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र का 30 फीसदी योगदान है। मध्य प्रदेश किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन) सहित अन्य योजनाओं में भारत में अग्रणी है। अगले माह मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में 21वीं पशु संगणना प्रारंभ होने वाली है। पशु संगणना में इस बार डाटा कलेक्शन का पूरा कार्य ऑनलाइन किया जाएगा। यह जानकारी आज प्रदेश में 21 वीं पशु संगणना 2024 की तैयारियों के संबंध में संचालनालय, पशु चिकित्सा एवं डेयरी के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में दी गई। कार्यशाला में भारत सरकार की मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय द्वारा पशु संगणना 2024 की तैयारियों के संबंध में ऑन लाइन संदेश दिया गया। कार्यशाला का शुभारंभ संचालक पशुपालन एवं डेयरी पीएस पटेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यशाला में पूरे प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य संबंधित उपस्थित थे।

पशुओं का विवरण दिया जाएगा

कार्यशाला में बताया गया कि 21वीं पशु संगणना मध्य प्रदेश के 55 जिलों के एक करोड़ 80 लाख परिवारों में घर-घर जाकर की जानी है। पशु संगणना में इस बार जब संगणक पशुओं की गणना करेंगे तब वे प्राप्त आंकड़ों को सीधे अपने टैब के माध्यम से पशु गणना सॉफ्टवेयर में भरेंगे। इस बार संगणना में पशुओं की नस्लों का भी विवरण दिया जाएगा। इसके लिए जब वे पशुओं का फोटो स्कैन करेंगे तब सॉफ्टवेयर के माध्यम से पशुओं की नस्ल की जानकारी मिल जाएगी।

728 शहरी वार्ड निर्धारित

पूरे प्रदेश में पशु गणना के लिए 5264 इकाई ग्राम एवं 728 शहरी वार्ड निर्धारित किए गए हैं। पशु संगणना के लिए ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक 3000 परिवार एक संगणक और शहरी क्षेत्र में प्रत्येक 4000 परिवार एक संगणक नियुक्त किए गए हैं। उनके ऊपर सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। कुल 5558 संगणक नियुक्त किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 4141 और शहरी क्षेत्र में 1417 संगणक बनाए गए हैं। कुल 970 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में 828 एवं शहरी क्षेत्र में 142 हैं।

प्रदेश में प्रभावी रणनीति

पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 21वीं पशुधन गणना के लिए मध्य प्रदेश में प्रभावी रणनीति बनाकर उसे कियान्वित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में पशुधन गणना के लिए कार्य प्रणाली और दिशा निर्देशों पर विस्तृत सत्र, मोबाइल एप्लीकेशन और डैश-बोर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण के साथ ही प्रतिभागियों के प्रश्न और समस्याओं का समाधान भी किया गया।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय बहुल 20 जिलों का किया गया चयन

लघु वनोपज के संग्रहण के लिए प्रदेश में 126 वन-धन विकास केंद्र बने

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय बहुल 20 जिलों में 126 वन-धन विकास केंद्र निर्मित किए जा चुके हैं। इन केन्द्रों में वर्तमान में 37 हजार 800 से अधिक सदस्य पंजीकृत हैं। वन-धन विकास केन्द्रों के जरिये लघु वनोपजों का सतत् रूप से संग्रहण, प्राथमिक स्तर का प्र-संस्करण एवं विपणन तथा बाजार की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर इन लघु वनोपजों का मूल्य संवर्धन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वनोपज संग्रहण का कार्य मुख्यत: प्रदेश में निवासरत जनजातीय समुदाय द्वारा ही किया जाता है। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना (पीएम जन-मन) में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के लिए कुल 198 वन-धन विकास केंद्र बनाए जाने हैं। इसके लिए प्रदेश के 24 पीवीटीजी बहुल जिलों में से 17 जिला लघु वनोपज यूनियन में अनूपपुर, अशोकनगर, उत्तर बालाघाट, दक्षिण बालाघाट, पूर्व छिंदवाडा, पश्चिम छिंदवाडा, दक्षिण छिंदवाड़ा, डिंडोरी, गुना, ग्वालियर, कटनी, पूर्व मंडला, पश्चिम मंडला, मुरैना, नरसिंहपुर, दक्षिण शहडोल, श्योपुर, सीधी, शिवपुरी, रायसेन एवं विदिशा को चिन्हित किया गया है।

जनवरी में मिली मंजूरी

वर्तमान में इन जिलों से करीब 1 करोड़ 47 लाख 65 हजार की लागत से बनने वाले 221 पीवीटीजी वन-धन विकास केंद्रों के निर्माण प्रस्ताव भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन एवं विकास संघ लिमिटेड नई दिल्ली एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। इसमें से ट्राईफेड द्वारा 57 पीवीटीजी वन-धन विकास केंद्र इसी साल जनवरी में ही मंजूर कर दिए गए हैं।

योजना पर एक नजर

वनोपजों के जरिये जनजातीय समुदायों की आय बढ़ाने और इन्हें वनोपज विक्रय के मुनाफे का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री वन-धन विकास योजना प्रारंभ की थी। इस योजना का क्रियान्वयन मप्र राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया जा रहा है। प्रदेश में पीएम वन-धन विकास योजना का क्रियान्वयन सुचारु रूप से वर्ष 2020 से प्रारंभ हुआ।

-मोहन सरकार कर रही अभूतपूर्व प्रयास

मध्यप्रदेश में श्रीअन्न के रकबे में तीन साल में हो गया दोगुना तक इजाफा

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्रीअन्न उगाने वाले किसानों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में की गई पहल से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया गया। प्रधानमंत्री की अभिनव पहल से श्रीअन्न के उत्पादन के क्षेत्र में देश और प्रदेश को नई दिशा मिली है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कृषि क्षेत्र में की गई पहल के लिए मुख्यमंत्री ने आभार माना है। उन्होंने कहा कि किसानों की परिश्रम से आज प्रदेश में श्रीअन्न का रकबा पिछले तीन साल में बढ़कर दोगुना हो गया है। मध्यप्रदेश में श्रीअन्न (मिलेट) के उत्पादन और उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं। राज्य सरकार के प्रयासों और किसानों के परिश्रम से मिलेट्स के रकबे में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2020-21 में जहां इसका रकबा 67 हजार हेक्टेयर था, वह वर्ष 2023-24 में बढ़कर 1.35 लाख हेक्टेयर रिकॉर्ड किया गया है। सीएम ने श्रीअन्न उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए रानी दुर्गावती श्रीअन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का फैसला किया है।

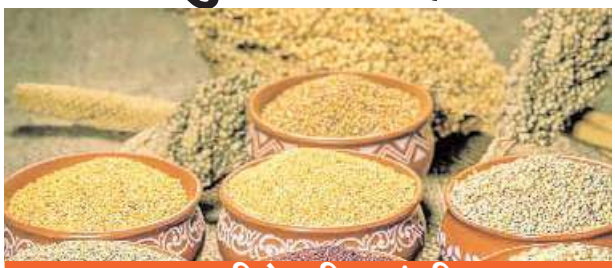

मप्र राज्य मिलेट्स मिशन संचालित

मध्यप्रदेश में श्रीअन्न के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही मध्यप्रदेश राज्य मिलेट्स मिशन संचालित है। प्रदेश में श्रीअन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फॉर्मर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड के नाम से मिलेट फेडरेशन का पंजीयन भी कराया गया है। प्रदेश में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में व्यापक तौर पर मनाया गया। मिलेट्स के उत्पादन और उपयोग के प्रोत्साहन के लिये निरंतर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। प्रदेश में मिलेट फसलें जैसे कोदो-कुटकी, ज्वार-बाजरा, रागी आदि किसानों द्वारा उगाई जाती है। इनमें कोदो-कुटकी की खेती मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों जैसे मंडला, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, छिन्दवाड़ा आदि जिलों में की जाती है। रागी की खेती प्रदेश में डिण्डोरी, मण्डला, सिवनी और जबलपुर में व्यापक तौर पर की जाती है। प्रदेश के खरगौन, खण्डवा, बड़वानी, छिंदवाड़ा, बैतूल, राजगढ़ और गुना जिले में ज्वार की खेती होती है।

मिलेट की ब्रॉण्डिंग भी की जा रही

प्रदेश में बाजरे की खेती मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र में होती है। मिलेट्स की खेती मुख्यतः खरीफ ऋतु में की जाती है। मिलेट्स के प्रोत्साहन के लिए 2023-24 में मप्र राज्य मिलेट मिशन द्वारा बीज वितरण, कृषक प्रशिक्षण, कृषक अध्ययन भ्रमण, सेमिनार एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर फूड फेस्टिवल, रोड-शो इत्यादि से मिलेट्स का प्रचार-प्रसार किया गया। इतना ही नहीं इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस एवं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में श्रीअन्न आधारित उत्पादों की शो-केसिंग की गई। भोपाल में हुए जी-20 सम्मेलन में श्रीअन्न आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना की नई दिल्ली में त्रिपक्षीय समीक्षा

सीएम मोहन बोले-पीएम के नेतृत्व में देश में नदी जोड़ो अभियान पर हो रहा काम

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली स्थित जल शक्ति मंत्रालय में पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना के संबंध में त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में नदी जोड़ो अभियान पर काम चल रहा है। इसी दिशा में मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना पर बड़े पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से दोनो राज्यों ने 20 वर्ष पुराने विवाद का हल निकाल लिया है और शीघ्र ही इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आशा व्यक्त की कि आने वाला समय मध्यप्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए अद्वितीय रहने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईआरसीपी लिंक परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) अनुबंध होने वाला है। दोनों राज्यों के हित में मध्यप्रदेश और राजस्थान मिलकर काम कर रहे हैं।

-50 गांवों में रोजाना दो लाख लीटर की सप्लाई

पशुधन से कहीं ज्यादा दूध के उत्पादन व खपत, खाद्य विभाग के निगरानी पर उठ रहे सवाल

भिंड में बेखौफ फल-फूल रहा मिलावटी दूध का कारोबार

भिंड। जागत गांव हमार

मिलावटी दूध की मंडी बने भिंड के 50 से ज्यादा गांवों में रोजाना दो लाख लीटर मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा है, जो मिश्रित दूध के नाम पर जिले से बाहर भेजा जाता है। यह स्थिति तब है जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में मिलावट करने पर 11 लोगों पर एफआइआर दर्ज कराई है। 14 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त किए हैं। वहीं 25 प्रतिष्ठान सील किए हैं। दूध और दूध से बने उत्पादों के 51 सैंपल फेल हुए हैं वहीं एक सैकड़ा से ज्यादा की जांच अभी पेंडिंग हैं। जिलेभर में एक लाख 45 हजार 489 पशु धन हैं। इनसे रोजाना 5 लाख 56 हजार 926 किग्रा लीटर दूध का उत्पादन होता है, जबकि रोजाना की खपत करीब 6.50 लाख किग्रा लीटर है। ऐसे में जिले में ही करीब 75 हजार लीटर मिलावटी दूध रोजाना खपाया जा रहा है। डेयरियों से टैंकरों में भरकर दूध को बाहर भेजा जाता है तो उन्हें 1 लीटर दूध पर 25 रुपए तक मुनाफा होता है। विशेषज्ञों ने इस दूध को बेहद खतरनाक बताया है। इससे आंत का कैंसर, लिवर और किडनी खराब होने का खतरा रहता है।

मिलावट करने वालों के खिलाफ हम लगातार अभियान चला रहे हैं। नौ माह में 300 से ज्यादा सैंपल लिए हैं। इसमें जो फेल होकर आए हैं उनके खिलाफ न्यायालय में प्रकरण लगाए हैं।
रीना बंसल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी भिंड

उपलब्धि पर राज्य के सीएम डॉ. मोहन यादव ने दी बधाई और शुभकामनाएं

-प्राणपुर, सावरवानी-लाडपुरा खास को केंद्र सरकार ने नवाजा

-8 श्रेणियों में देश के 36 गांव बने विजेता, मप्र के तीन शामिल

मध्यप्रदेश के तीन गांवों को मिला श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का खिताब

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के अंतराष्ट्रीय पर्यटन दिवस पर तीन गांवों को विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया है। प्राणपुर को शिल्प श्रेणी में और सावरवानी एवं लाडपुरा खास को जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ये गांव भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 में विजेता रहे हैं। प्राणपुर चंदेरी में, लाडपुरा खास निवाड़ी और सावरवानी छिंदवाड़ा जिले में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश के तीन ग्रामों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों की प्रतियोगिता की शुरुआत की गई थी। इस पहल का मकसद उन गांवों की पहचान करना और उन्हें चिन्हित करना था, जो समुदाय-आधारित मूल्यों और सभी पहलुओं में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के ज़रिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक संपत्ति को संरक्षित करते हैं और बढ़ावा देते हैं। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में, 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 की 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया।

300 विदेशी पर्यटक आए: छिंदवाड़ा के तमिया विकासखंड के झिरपा से 6 किलोमीटर अंदर 300 घरों का सावरवानी गांव 2019 में पर्यटन गांव बना है। अब तक यहां 300 से ज्यादा विदेशी पर्यटक भी आकर गांव की संस्कृति, खान- पान की संस्कृति से अवगत हुए है। खेती-किसानी, पशुपालन की गतिविधियों में पर्यटक स्वयं शामिल भी हुए। पर्यटकों में दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, यूरोप, रूस, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के नागरिक शामिल है।

सफाई पर फोकस

सावरवानी में वे सब सुविधाएं हैं जो आदर्श गांव के लिए अनिवार्य हैं। सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गांवों की शांति और प्राकृतिक परिवेश पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है। यहां शांत वातावरण में रुक कर आसपास के प्राकृतिक पर्यटन स्थल जैसे अनहोनी गर्म कुंड, अनहोनी मेला, सप्तधारा, चांवलपानी के पास स्थित खारा पानी दैविक कुंड, घोघरा वाटरफाल, तामिया, पातालकोट, मौनीबाबा की पहाड़ी के साथ झिंगरिया वाटरफाल की सैर कर पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन का बरगोदी गांव इससे सटा हुआ है।

डिनर का पूरा पैकेज

पर्यटकों के लिए ब्रेक फास्ट, लंच और डिनर का पूरा पैकेज है। इसके अलावा बैलगाड़ी की सैर, गायों का दूध दुहना, उन्हें चारा खिलाना, खेती किसानी के छोटे-छोटे काम करना और पास की मोनाखेड़ी पहाड़ी में ट्रैकिंग की सुविधा, भजन मंडली और जनजातीय करमा नृत्य मंडली भी उपलब्ध होने से सावरवानी में रुकना यादगार बन जाता है और स्मृति लंबे समय तक बनी रहती है।

अपर प्रबंध संचालक मुखर्जी ने ग्रहण किया सम्मान

-राज्य मंत्री लोधी ने दी बधाई और शुभकामनाएं

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित हुए समारोह में मप्र टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी ने ग्रामीण प्रतिनिधियों के साथ यह सम्मान ग्रहण किया। पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने इस उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश पर्यटन के ग्रामीण पर्यटन के विकास के क्षेत्र में किया जा रहे प्रयासों को सराहने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा व गांव की अर्थव्यवस्था का विकास होगा। गांवों में प्राचीन कला, शिल्प और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण होगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों तक यह धरोहर सुरक्षित रहेगी।

विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी

अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में सम्मानित होने से प्राणपुर, सावरवानी व लाड़पुरा खास को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी। देशी-विदेशी पर्यटकों के आगमन में बढ़ोतरी होगी। उल्लेखनीय है कि, 2023 में पन्ना जिले का मडला एवं सीधी जिले का खोखरा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया था।

बुनकरों और शिल्पकारों का ग्राम प्राणपुर

प्राणपुर गांव, चन्देरी की तराई में लगभग चार किमी दूरी पर सुरम्य स्थल है। इस गांव की विशेषता यह है कि गांव के 243 घर बुनाई कला से जुड़े हैं। वे हथकरघे का उपयोग दो-तीन पीढ़ियों से कर रहे हैं। गांव के पचास से अधिक शिल्पकार बांस, लकड़ी, पत्थर, गहनें तथा मिट्टी के शिल्प से जुड़े हैं। यह पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र है। गांव के पुराने कच्चे पहुंच मार्ग की मरम्मत स्थानीय पत्थरों का से की गयी है। गांव के अन्दर पर्यटक अपने वाहनों से जाकर एक नियत स्थान पर उतरकर आकर्षक गांव का भ्रमण करते हैं। यहां पर एक पार्किंग स्थल भी विकसित किया गया है। पर्यटकों के लिए विशेष रूप से एक कैफेटेरिया हेंडलूम कैफे का निर्माण किया गया है। यहां महिला, पुरुष एवं दिव्यांगजनों के लिये जनसुविधाओं एवं पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है। पर्यटकों की सुविधाओं एवं मनोरंजन के लिए बगीचा विकसित किया गया है। जिसमें एम्फीथियेटर का निर्माण भी किया गया है। यहां स्थानीय समुदाय के सांस्कृतिक दल समय-समय पर पर्यटकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे।

तीन गांवों का चयन गर्व की बातः शुक्ला

प्रमुख सचिव पर्यटन व संस्कृति विभाग एवं प्रबंध संचालक मप्र टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि हमें गर्व है कि प्रदेश के प्राणपुर, सावरवानी और लाड़पुरा खास ग्राम को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में चयनित किया गया है। यह उपलब्धि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन गांवों में न केवल स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण किया गया है, बल्कि पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास भी किए गए हैं। हम इस पहल को और आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्पित हैं, ताकि राज्य के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को भी विश्व पर्यटन मानचित्र पर उचित स्थान मिल सके।

सम्मानित ग्रामों का संक्षिप्त विवरण

प्राणपुर के बारे में जिला अशोकनगर की तहसील चंदेरी से 4 किमी दूर प्राणपुर को मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा देश के पहले क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज के रूप में विकसित किया गया है। यहां बुनकरों के लगभग 243 घरों में हथकरघा बुनाई का कार्य किया जाता है, गांव में लगभग 550 हाथकरघों पर लगभग 900 बुनकर चन्देरी वस्त्रों की बुनाई करते हैं। 06 मार्च 2024 को म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, केन्द्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया द्वारा परियोजना का शुभारंभ किया गया था।

सावरवानी के बारे में छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में बसा सावरवानी गांव समृद्ध गोंड जनजातीय संस्कृति को दर्शाता है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन से घिरा यह गांव शांत वातावरण, पक्षियों की प्रचुर प्रजातियां और मनोरम परिदृश्यों से भरा हुआ है। यहां टूरिज्म बोर्ड द्वारा 9 होम-स्टे तैयार किए जा चुके हैं। विलेज वॉक, प्राकृतिक खेती, बैलगाड़ी की सवारी, मछली पकड़ना, पक्षी देखना, साइकिल चलाना, स्टारगेजिंग जैसी गतिविधियों का आनंद लेते हैं। मक्के की रोटी, चने की भाजी और चना दाल जैसे स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं।

लाड़पुरा खास के बारे में निवाड़ी जिले में ओरछा से 8 किलोमीटर दूर स्थित लाड़पुरा खास को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत पहले ग्रामीण पर्यटन गांव होने का गौरव प्राप्त है। बुंदेलखंड सांस्कृतिक क्षेत्र के केंद्र में बसा लाड़पुरा खास मेहमानों को बेहतरीन बुंदेली संस्कृति और परंपराओं से अवगत कराने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। मनमोहक परिदृश्यों, वादियों, कृषि क्षेत्रों और ग्रामीण जीवन से घिरा लाड़पुरा खास प्रकृति के सुरम्य नजारों से भरपूर है। स्थानीय वास्तुकला में निर्मित और हाथ से बनाई गई दीवार पेंटिंग से सजे होम-स्टे, लाड़पुरा खास के आकर्षण हैं।

एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बदल रहा किसानों का जीवन

शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का किसानों के प्रति गहरा प्रेम और संवेदनशीलता, उनके द्वारा लिए गए निर्णय, नीतियों और योजनाओं में स्पष्ट नजर आती है। अन्नदाताओं का जीवन बदलना ही उनका प्रथम लक्ष्य है और संकल्प भी। यही कारण है कि सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में कृषि और किसान सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रहे। उनके नेतृत्व में, सरकार किसानों के सशक्तीकरण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए अभूतपूर्व प्रयास कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी नीतियों में स्पष्ट रूप से झलकता है। भारत में फसल के बाद होने वाला नुकसान बड़ी चुनौती है, जो कृषि क्षेत्र की क्षमता और लाखों किसानों की कड़ी मेहनत को प्रभावित कर रहे हैं। अनुमानों के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष इसके कुल खाद्य उत्पादन का लगभग 16-18प्रतिशत नष्ट हो जाता है।

खाद्य पदार्थों के नष्ट होने का प्रमुख कारण उचित भंडारण की कमी, कोल्ड चेन और अपर्याप्त प्रसंस्करण इकाइयाँ, कुशल लॉजिस्टिक्स का अभाव इन बड़े नुकसानों में योगदान करते हैं, जिससे देश की समग्र खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए इन्हे मजबूत करने की दिशा में मोदी सरकार नए सिरे से काम कर रही है।

कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए नवाचार के नित नये उपाय किये जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के शोध को लैब से लैंड तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिससे किसानों की उत्पादन की लागत घटे और फायदा ज्यादा हो। प्रधानमंत्री दूरदृष्टा हैं जिनके द्वारा जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में एआईएफ की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने और खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के लिए कृषि परिसंपत्तियों के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन परियोजनाओं और नए युग की तकनीकों को बढ़ावा देकर इन चुनौतियों का समाधान करना है। एआईएफ के तहत, बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3ब प्रति वर्ष की ब्याज छूट और सीजीटीएमएसई के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। इस पहल के माध्यम से सरकार का उद्देश्य न केवल उपज की गुणवत्ता और मात्रा को संरक्षित करना है, बल्कि किसानों को बाजारों तक अधिक कुशलता से पहुँचने में सक्षम बनाना है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी।

प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व के परिणामस्वरूप अगस्त 2024 तक योजना के लाभ के लिए पात्र 35,747 करोड़ रुपये सहित इस योजना के तहत स्वीकृत राशि 47,500 करोड़ रुपये को पार कर चुकी है और 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का वितरण हो चुका है। उल्लेखनीय रूप से स्वीकृत परियोजनाओं में से 54प्रतिशत योजनाएं किसानों, सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई हैं, जो प्रधानमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप खेत-स्तर के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में किसानों की मजबूत भागीदारी को प्रदर्शित करती हैं।

कृषि उपज का फसलोपरांत नुकसान का समाधान हो सके, इस दिशा में प्रधानमंत्री मोदी अत्यंत गंभीर है। उन्होंने भंडारण (ड्राई और कोल्ड), परिवहन आदि में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी है, ताकि किसानों को फसल नुकसान से बचाया जा सके। शुष्क भंडारण के संदर्भ में, खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में भारत में 1740 लाख मीट्रिक टन क्षमता के स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वर्तमान में भारत में कुल अनाज उत्पादन की भंडारण क्षमता 44प्रतिशत है, जो बहुत कम है। इसी प्रकार बागवानी उत्पादों के लिए भारत में लगभग 441.9 लाख मीट्रिक टन भंडारण की कोल्ड चेन क्षमता है जो देश में फलों और सब्जियों के उत्पादन का केवल 15.72प्रतिशत है। इन पूर्ण परियोजनाओं ने क्षेत्र की भंडारण क्षमता में लगभग 500 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की है। परिणामस्वरूप, नई शुष्क भंडारण सुविधाएं प्रति वर्ष 18.6 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का संरक्षण कर रही हैं, जिससे लगभग 5,700 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उचित कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के विकास से बागवानी उत्पादों के नुकसान में 10प्रतिशत की कमी आई है, जिससे फसलोपरांत 3.5 लाख मीट्रिक टन उपज सुरक्षित हो रही है और हर साल लगभग 1,250 करोड़ रुपये की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री का कृषि क्षेत्र और किसानों के प्रति यह समर्पण न केवल उनके आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में है, बल्कि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में एआईएफ से कृषि अवसंरचनाओं के विकास को नई गति मिली है। अगस्त 2024 तक, एआईएफ के तहत देश भर में एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित 74,695 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर में 18,508 कस्टम हायरिंग सेंटर, 16,238 प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र, 13,702 गोदाम, 3,095 छंटाई और ग्रेडिंग इकाइयां, 1901 कोल्ड स्टोर और कोल्ड चेन और 21,251 अन्य प्रकार के एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। 74,695 परियोजनाओं की मंजूरी से कृषि क्षेत्र में कुल 78,702 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है, जो महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्राथमिकता दी है, बल्कि युवाओं और किसानों के बीच उद्यमशीलता को भी प्रोत्साहित किया है, जिससे लगभग 50,000 नए कृषि उद्यम स्थापित हुए हैं। सरकार के प्रयासों से युवा भी कृषि की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जो किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इन प्रयासों ने 800,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए हैं और भविष्य में यह संख्या और भी बढ़ेगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 2.5 मिलियन नौकरियों का सृजन होगा।

सरकार की कल्याणकारी नीतियों से किसानों की कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव आया है। खेत पर उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से किसानों को सीधे व्यापक उपभोक्ता आधार को बेचने की सुविधा मिली है, जिससे मूल्य प्राप्ति में वृद्धि हुई है और उनकी समग्र आय में वृद्धि हुई है। आधुनिक पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सिस्टम के कारण किसान अपनी बाजार बिक्री को समयबद्ध ढंग से अधिक रणनीतिक रूप से कर सकते हैं, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति होती है। औसतन, इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने किसानों को अपनी उपज के लिए 11-14प्रतिशत अधिक मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।

सरकार की नीतियाँ न केवल एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को प्रोत्साहित कर रही हैं, बल्कि ऋण जोखिम को भी कम कर रही हैं। क्रेडिट गारंटी समर्थन और ब्याज छूट के माध्यम से ऋण देने वाली संस्थाएं न्यूनतम जोखिम के साथ ऋण दे सकती हैं, जिससे उनके ग्राहक आधार और पोटफ़ेलियो डाइवर्सिफिकेशन का विस्तार करने में सहायता मिलती है। विशेष रूप से, इस फंड ने नाबार्ड की पुनर्वित्त सुविधा के साथ मिलकर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में शामिल प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के लिए प्रभावी ब्याज दर को घटाकर 1प्रतिशत कर दिया है। इससे इन पैक्स से जुड़े हजारों किसानों को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। आज तक, एआईएफ के तहत 2,970 करोड़ रुपए के ऋण के साथ 9,573 पैक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें नाबार्ड से सैद्धांतिक मंजूरी भी शामिल है। एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्र सरकार ने महत्वाकांक्षी एआईएफ योजना में प्रगतिशील वृद्धि की एक श्रृंखला शुरू की है, जिससे यह अधिक समावेशी और काफी हद तक अधिक प्रभावशाली बन गई है। सरकार का प्रयास है कि कृषि लाभ का धंधा बने और किसानों की आय बढ़े।

नीमः एक महत्वपूर्ण जैविक कीटनाशी औषधीय वृक्ष

» डॉ. रिया ठाकुर
» डॉ. चंचल भार्गव
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय , कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश

नीम एक महत्वपूर्ण औषधीय वृक्ष है, जिसका भारतीय संस्कृति और आयुर्वेद में विशेष स्थान है। इसके पेड़ के पत्ते, छाल, फल, और तेल, सब उपयोगी है। नीम में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो इसे त्वचा रोग, दंत समस्याओं, और संक्रमण के इलाज में प्रभावी बनाते हैं। इसका उपयोग मलेरिया, डायबिटीज, और पाचन तंत्र के रोगों में भी होता है। कृषि में नीम का तेल जैविक कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त होता है, जो फसलों को हानिकारक कीटों से बचाता है। नीम का पेड़ पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि यह वायु को शुद्ध करता है।

नीम कीटनाशियों के गुण: पौधों, पशुओं, स्तनधारियों, पानी, मिट्टी व पर्यावरण के लिये पूर्ण सुरक्षित होते हैं। इनमें जैव क्रियाशीलता धीमी, टिकाऊ व बिना अवशेषी प्रभाव वाली होती है। सुगमता से उपलब्ध है तथा कम समय में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कम खर्चीले होते हैं । इनको सुगमता से कच्चे माल से प्राप्त किया जा सकता है। उत्पाद की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी करते हैं तथा उपज में भी बढ़ोत्तरी होती है। अध्ययनों से यह भी ज्ञात हुआ है कि पौध उत्पाद मित्र कीट व सूक्ष्म जीवाणु पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ता है। इनको किसान स्वयं तैयार कर सकता है। क्योंकि इसके लिये विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। उत्पादन लागत कम होती है।

हमारे देश में नीम के पौधे विस्तृत रूप से पाये जाते है। जिसके विभिन्न उत्पादों से कीट व्याधियों का नियंत्रण आसानी से किया जाता सकता है। वर्तमान में नीम आधारित बहुत से उत्पाद बाजार में उपलब्ध हैं। देश में ऐसी प्रौधोगिक इकाईयाँ है जो विभिन्न उत्पादों का उत्पादन कर रही है। अब हमारे लिए आवश्यक है कि हम इन्हीं उत्पादों का उपयोग दिनों-दिन अनुसंधानों द्वारा बढ़ायें एवं कृषकों को इनकी उपयोगिता के बारे में विस्तार एवं प्रसार के द्वारा विस्तृत जानकारी दें। जिनके द्वारा कृषक भाई इन नीम एंव नीम के उत्पादों को अपनी खेती की तकनीक में सम्मिलित करना चाहिए। इससे समेकित नाशीजीव प्रबंधन, जैविक खेती एवं पर्यावरण संतुलन के मूल भूत सिद्धातों को बल मिलेगा।

नीम का कीटों पर प्रभाव: नीम के उत्पाद कीटों की विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावित करते हैं। नीम के वृक्ष से तैयार किये जाने वाले विभिन्न उत्पाद कीटों के लिये बहुउपयोगी हारमोन्स का - आकार प्रकार पर निर्धारण करते हैं। कीटों का शरीर इन नीम के तत्वों को सोख लेता है। ये हार्मोन्स प्रणाली को सुचारू रूप से चलने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं तथा कीटों के स्वभाव एवं शरीर में परिवर्तन पैदा करते हैं। जिससे कीटों का मस्तिष्क एवं प्रजनन कार्य करने के लिये व्यवधान उत्पन्न हो जाता है एवं उनकी संख्या सीमित रह जाती है। यही प्रभाव नीम के सत्व में देखने को मिला। अनुसंधान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभिन्न नीम के उत्पादों का उपयोग एवं कार्यक्षमता कीटों के प्रबंधन में विभिन्न रूप से कार्य करती हैं।

1. अण्डों, इल्ली एवं शंखी के वृद्धि को रोकना एवं नष्ट करना। **2.** इल्ली में शारीरिक परिवर्तन की क्रिया को प्रतिबंधित करना। **3.** मैथून आदान प्रदान के संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करना । **4.** इल्ली एवं व्यस्क में अलगाव पैदा करना। **5.** मादा में अण्डा देने की प्रकृति को अक्षम या कम करना। **6.** इल्ली एवं वयस्क में विषैले प्रभाव के द्वारा अक्षमता लाना। **7.** वयस्क में नपुंसकता पैदा करना। **8.** निगलने की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न करना। **9.** भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में परहेज करना। **10.** कायटिन नाम पदार्थ के निर्माण में अवरूद्ध पैदा करना।

उत्पादन तकनीकी: फलों को एकत्रित करना: पके हुए फलों को हाथ से चुनकर तोड़ सकते हैं तथा टूटे हुए फलों को एकत्रित कर सकते हैं। यदि पेड़ के नीचे सफाई हो तो झाड़ू द्वारा भी एकत्रित किया जा सकता है। सड़े गले फलों को हटा देना चाहिए। फलों को रोज प्रात: एकत्रित करना चाहिए।

कीटनाशक के रूप उपयोग विधि: फसलों में नीम का मुख्य उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है।

फसलों पर रस चूसक कीटों से बचाव के लिए वर्टीसिलियम लैकानी 75 ग्राम व नीम तेल 30 मिली का छिड़काव 15 लीटर पानी में मिलाकर करें।

नीम के तेल की 2 प्रतिशत मात्रा को पानी में मिलाकर फसलों में 7 से 10 दिन के अंतराल में छिड़कने से कीट जनित रोग नहीं लगते। इसके अलावा इसके घोल का छिड़काव पौधों पर करने से वायरस जनित पाउडरी मिल्डयू जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलाता है। हैं। टिड्डी की रोकथाम के लिये नीम तेल का उपयोग कीट की चौथी अवस्था में किया जाता है तो इसके परिणाम शत प्रतिशत मिले हैं।

रस चुसक कीटों के लिए ताम्बे के पात्र में 10 लीटर छाछ उसमें 500 ग्राम नीम की निबोली कूटकर डालें। 1 किलो धतुरा के पत्ते कूटकर डाले और 15 दिन बाद 1 लीटर को 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।

नीम की पत्तियों को पानी में 1:2 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण बना लें उसके बाद मिश्रण को 10 प्रतिशत पानी बचने तक उबालकर उसका अर्क तैयार कर लें इस अर्क को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कने से भूरा फुदका, रस चूसने वाले कीटों और हरा फुदका जैसे रोग नहीं लगते।

ग्रीनहाउस गैसों व बढ़ते तापमान पर लगाम लगाने में उपयोगी हो सकती है नई कृषि पद्धति

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और कृषि पर किए गए शोधों से एक जटिल दो-तरफा संबंध का पता चला है। कृषि के कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन, विलुप्ति और प्रदूषण के लिए जिम्मेवार है और साल-दर-साल पर्यावरण पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है। साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़, सूखा और बढ़ता तापमान दुनिया भर में फसलों के उत्पादन को खतरे में डालने लगे हैं।

कृषि से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन अब 1960 के दशक की तुलना में 18 गुना अधिक हो गया है, जो दुनिया में तापमान वृद्धि का लगभग 30 फीसदी है। खेत में छोड़े गए अतिरिक्त उर्वरकों को बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रस ऑक्साइड बनाने के लिए तोड़ा जाता है, जो एक ग्रीनहाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना अधिक शक्तिशाली है।

अधिक पैदावार बनाए रखने के साथ खेती के कारण तापमान में बढ़ोतरी को कम करने के लिए रणनीतिक प्रयास जलवायु परिवर्तन को कम करने और हमारे खाद्य आपूर्ति को इसके प्रभावों से बचाने के लिए जरूरी हैं। मिनेसोटा विश्वविद्यालय और दुनिया भर के 20 से अधिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर किए गए इस शोध में जलवायु और खेती के बीच संबंधों की जांच की गई है। साइंस में प्रकाशित शोध में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन दुनिया की खाद्य आपूर्ति पर अधिक दबाव डालता है, कृषि में ऐसी पद्धतियों को अपनाया जा रहा है जो जलवायु परिवर्तन को और तेज कर रही हैं। शोध में शोधकर्ताओं ने नई कृषि पद्धतियों की भी पहचान की है जो आने वाले दशकों में जलवायु के प्रभावों को बहुत कम करने, दक्षता बढ़ाने और हमारी खाद्य आपूर्ति को स्थिर करने की क्षमता रखती हैं। शोधकर्ताओं ने शोध में पाया कि जलवायु परिवर्तन का खेती करने की पद्धतियों पर भारी प्रभाव पड़ता है, पानी का उपयोग और कमी बढ़ती है, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन उत्सर्जन, मिट्टी का क्षरण, नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रदूषण, कीट दबाव, कीटनाशक प्रदूषण और जैव विविधता का नुकसान होता है। खेती की वजह से कृषि से संबंधित ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन बढ़ सकता है। कृषि में बदलाव के बिना, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से दो डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को हासिल करना असंभव बना सकता है।

उमरिया जिले के पठारीकला गांव के जनजातीय ग्रामीणों ने ली शपथ

न बनाएंगे - न पीएंगे शराब, पकड़े गए तो भरेंगे 10 हजार जुर्माना

भोपाल। जागत गांव हमार

आत्मशुचिता (स्वच्छता) सबके लिये बेहद जरूरी है। मानव तन-मन के विकास में ही समाज का विकास निहित है। भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा अभियान की तरह नशा मुक्ति अभियान की सफलता भी प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में साफ-साफ दिखाई देने लगी है। उमरिया जिले की करकेली जनपद पंचायत क्षेत्र के पठारीकला गांव में पूरे गांव ने नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। गांव के सभी जनजातीय ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर शराब न बनाने और इसका सेवन भी कतई न करने की शपथ ली। अभियान की सफलता के लिए ग्रामीणों ने कंधे से कंधा मिलाकर यह सामाजिक संकल्प लिया। सामाजिक संकल्प के साथ गांव के लोगों ने लिखित शपथ-पत्र भी दिया। शपथ-पत्र में साफ-साफ लिखा है कि हम आज से न कभी शराब पियेंगे और न ही बनायेंगे और अगर ऐसा करते पाये गये, तो 10 हजार रुपए का अर्थदंड देंगे। इस मौके पर गांव के सरपंच गोविंद सिंह मरावी, जनपद सदस्य संतराम सिंह परस्ते, रामपाल सिंह बडकरे, रूपशाह मरकाम, बारेलाल सिंह बडकरे, लालशाह बैगा, देवीदीन बैगा, सुदामा सिंह, जगत प्रसाद बैगा, शीतल बैगा, बसंत बैगा, रामनारायण सिंह, मंगल सिंह, रघुनाथ सिंह, कृष्ण कुमार सिंह, नत्थू बैगा, गीता बाई, ममता बाई, शकुंतला बाई, रामवती बाई, फूलबाई सहित अन्य जनजातीय ग्रामीणों ने यह शपथ ली।

नशे की बढ़ती लत बेहद चिंतनीय

गांव के प्रबुद्धजनों एवं जागरूक लोगों ने इन ग्रामीणों को बताया कि कोई भी नशा या बुरी आदत समाज एवं परिवार को पतन की ओर ले जाता है। नशा और बुरी आदतें घर की सुख-समृद्धि एवं बच्चों की शिक्षा को पूरी तरह नष्ट कर देता है। हम सभी नशामुक्त होकर स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण में भागीदार बनें। साथ ही बच्चों की शिक्षा पर भी पूरे समर्पण से ध्यान दें, तभी हम अपने गांव, जिले, प्रदेश और देश को नशामुक्त बना पाएंगे। उल्लेखनीय है कि समाज में शराब का सेवन और दूसरे प्रकार के नशे की बढ़ती लत बेहद चिंतनीय है। कई आपराधिक घटनाओं, दुर्घटनाओं के पीछे शराबखोरी और नशे की लत बड़ी वजह के रूप में सामने आती हैं। नशा मुक्ति अभियान को लेकर जब हम सभी जागरूक होंगे, तभी आपराधिक घटनाएं एवं दुर्घटनाएं रुकेंगी।

दुग्ध उत्पादकों की मांग पर फैट के भाव में 20 रु. प्रति किलो की हुई वृद्धि

उज्जैन दुग्ध संघ ने मप्र के पहले डेयरी कॉलेज का प्रस्ताव किया अनुमोदित

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के विजन अनुरूप प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों की उन्नति, आय में वृद्धि, प्रदेश में नई श्वेत क्रान्ति लाने, उच्च नस्ल के पशुओं की उपलब्धता बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन की लाभप्रदता की वृद्धि, डेयरी टेक्नोलॉजी उच्च कौशल प्राप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता और डेयरी टेक्नोलॉजी में आधुनिकता लाने के लिये शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए उज्जैन में प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज स्थापित किए जाने के प्रस्ताव का सर्व-सम्मति से अनुमोदन दुग्ध संघ की वार्षिक साधारण सभा में किया गया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की दूरदर्शी योजना के तहत डेयरी उत्पादन में आधुनिक तकनीक का प्रयोग, मशीनीकरण व उच्च स्तरीय मानव संसाधन प्रबंधन किया जा रहा है। दुग्ध संघ समितियों एवं दुग्ध उत्पादक किसानों के कल्याण, आय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने, दुग्ध संकलन को दोगुना करना, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और मध्यप्रदेश दुग्ध फेडरेशन के समझौते का उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर अनुमोदन किया गया।

वृद्धि के बाद नए भाव 740 रुपए प्रति किलो फैट होंगे

उज्जैन दुग्ध संघ की 43वीं वार्षिक साधारण सभा में दुग्ध समितियों एवं दुग्ध उत्पादकों की प्रमुख मांग दूध के प्रति किलो फैट के भाव में वृद्धि किए जाने की मांग को पूरा करते हुए 20 रुपए प्रति किलो फैट की वृद्धि की गई। वृद्धि के बाद नए भाव 740 रुपए प्रति किलो फैट होंगे। संभागायुक्त एवं प्रशासक दुग्ध संघ गुप्ता ने कहा कि उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उच्च गुणवत्ता का दूध एवं दुग्ध के उत्पाद के निरन्तर उपलब्ध कराने पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा दुग्ध संघ को सर्वोच्च श्रेणी 'ए+' प्रदान की गई है। इसी क्रम में इंडियन डेयरी एसोसिएशन पश्चिम क्षेत्र द्वारा नागपुर में आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस में केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा उज्जैन दुग्ध संघ को बेस्ट डेयरी प्लांट की श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया है। उक्त उपलब्धियों के लिए संभागायुक्त गुप्ता ने सभी सदस्य महानुभावों को शुभकामनाएं दी।

मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का उत्तम साधन-डॉ. अखिलेश

रीवा। जागत गांव हमार

यूनियन ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सगरा, रीवा के निदेशक एमजे राव के निर्देशन में मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 22 सितंबर से 01 अक्टूबर 2024 तक किया गया है।

कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक अरुण द्विवेदी हैं जो तकनीकी एवं प्रायोगिक तौर पर मधुमक्खी पालकों को प्रशिक्षण दे रहे है। कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा के वैज्ञानिक डॉ. अखिलेश कुमार को अतिथि लेक्चर देने के लिए आमंत्रित किया गया जिन्होंने इस अवसर पर बताया कि जिन किसान भाइयों के पास जमीन नहीं है वो भी आसानी से मधुमक्खी पालन कर सकते है। डॉ. कुमार ने कहा कि मधुमक्खियों से फसलों, फलो में अधिक उत्पादन के साथ गुणवत्ता में भी सुधार होता है। साथ ही साथ अतिरिक्त उत्पाद मधु, रॉयल जेली, मौम, प्रोपोलीस, विष इत्यादि प्राप्त होती है। इस प्रकार कृषक मधुमक्खि पालन करके अतिरिक्त आय ले सकता है। इस अवसर पर अखिलेश मिश्रा और प्रगतशील किसान उपस्थित रहे।

मशरूम उत्पादन से बढ़ने लगी किसानों की आया, दिया प्रशिक्षण

टीकमगढ़

योजना कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा विकसित भारत संकल्प 2047 अंतर्गत 100 दिवसीय कार्य योजना अंतर्गत पांच दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रशिक्षण डॉ. बीएस किरार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख के मार्गदर्शन में डॉ. आरके प्रजापति नोडल अधिकारी(मशरूम प्रशिक्षण) एवं जयपाल छिगारहा द्वारा संपन्न कराया गया है। केंद्र द्वारा 2019-20 से कृषि में नवाचार के रूप में मशरूम उत्पादन के कौशल विकास प्रशिक्षण को एक जलवायु परिवर्तन के दौर में कृषि में जुड़े व्यवसायियों पर प्रशिक्षण करता आ रहा है जिससे अब जिले में मशरूम का उत्पादन बहुत लोग करने लगे हैं जिसमें दो महिलाएं स्वा-सहायता समूह और एक स्वयं कृषि फार्म द्वारा मशरूम के उत्पादन में लगे हुए हैं। मशरूम की शुरुआत टीकमगढ़ में पहले धीमी हुई जहां पहले लोगों की सोच में मशरूम को एक कुकुरमुत्ता तक सीमित थी। वही आज लोगों को मशरूम आकर्षित करता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि मशरूम को लेकर लोगों में जागरूकता आई है। साथ ही मशरूम अध्ययन टीकमगढ़ के लोगों को आसान आय के साधन एवं स्वास्थ्य वर्धक है। मशरूम उत्पादन के लिए टीकमगढ़ जिले की जलवायु अनुकूल है। यहां पर उपस्थित फसलों के भूसे जैसे गेहूं, उड़द, सोयाबीन, चना, मसूर, एवं मटर इत्यादि पर उगने की क्षमता एवं मशरूम उगाने की सरल विधि के कारण तेजी से लोगों को आकर्षित कर रहा है। मशरूम खाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में भी लोगों में जागरूकता हो रही है। अभी तक टीकमगढ़ में डिंगरी (ओयस्टर), बटन और दूधिया मशरूम की खेती सफलतापूर्वक की जा चुकी है। आने वाले समय में महंगे मशरूम की खेती पर केंद्र द्वारा शोध किया जा रहा है। मशरूम की खेती भूमिहीन लोग एक छोटे से कमरे में 250-300 रुपए लगाकर शुरुआत कर सकते हैं। टीकमगढ़ जिले में कृषकों, युवा, महिला जिसको भी मशरूम उत्पादन में रुची है वो कृषि विज्ञान केंद्र में अपना नाम पंजीकृत करवा सकते है। जिससे जब भी मशरूम प्रशिक्षण होगा।

सावधान...फसल अवशेष प्रबंधन आने वाले समय में अत्यंत आवश्यक

शहडोल। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र शहडोल एवं कृषि अभियांत्रिकी विभाग शहडोल के सामंजस्य से ग्राम बंडीकला में कृषकों को फसलों के अवशेषों के प्रबंधन के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी इस कार्यक्रम में वैज्ञानिक दीपक चैहान द्वारा कृषकों को जानकारी दी की अभी खरीफ की फसल की कटाई होने के बाद उसके बचे हुए अवशेषों को उचित तरीके से प्रबंधन करना अति आवश्यक है। हालांकि शहडोल में फसलों के अवशेषों को आग नहीं लगाई जाती है परन्तु किसान समय के आभाव में आग लगाते है परन्तु यह एक जुर्म है।

धान की फसल की कम्बाईन हार्वेस्टर से कटाई के बाद समय के आभाव के कारण किसान गेहूं की फसल की बोवनी से पहले

किसान फसल के अवशेष को आग लगा देते है जिससे खेतों को नुकसान होता है। साथ ही मनुष्य एवं पशु-पक्षियों की सेहत पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आग लगाने से मिट्टी के पोषण तत्त्व नष्ट होते हैं। मिट्टी की ऊर्वरा शक्ति पर भी प्रतिकल प्रभाव पड़ता है। धान के अवशेष को जलने से 70 प्रतिशत कार्बन डाईऑक्साइड, 7 प्रतिशत कार्बन मोनोऑक्साईड, 0.66 प्रतिशत मीथेन व 2.09 प्रतिशत नाइट्रेट ऑक्साइड गैस निकलती है जो की वातावरण में कई तरह के बदलाव लाने का कारण बनती है। पराली प्रबंधन में आधुनिक कृषि यंत्र काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। फसल अवशेष प्रबंधन में प्रयोग होने वाले यह सात उपकरण (जीरो टिल सीड ड्रिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रोटावेटर, मल्चर, स्ट्रा बेलर एवं सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम) आमतौर पर किसानों के लिए किसी हथियार से कम नहीं है। जो खेती बचाने, लोगों के जीवन को स्वस्थ रखने में मदद कर रहे हैं। पराली के मिट्टी में मिलने से खेत की उर्वरक शक्ति बढ़ती है जिससे आने वाली फसल की लागत कम हो जाती है। वहीं किसानों को आर्थिक तौर पर फायदा मिलता है।

भूमि की नमी एवं उर्वरा शक्ति बनी रहती है ...

मशीनों के इस्तेमाल से गेहूं की बिजाई भी हो जाती है। साथ ही आने वाली फसल में पानी कम लगता है। कृषि अभियांत्रिकी विभाग के सहायक कृषि यंत्री शहडोल रितेश प्यासी ने बताया की सुपर सीडर मशीन के उपयोग से खेत में नरवाई जलाने की आवश्यकता एवं खेत तयार करने की आवश्यकता नहीं होती है जिससे समय की भी बचत होती है और भूमि की नमी एवं उर्वरा शक्ति बनी रहती है। मशीन की खरीद पर केंद्र सरकार एवम राज्य सरकार की अनुदान योजनाओं पर 105000/- तक का अनुदान है। इसी तरह कृषक स्ट्रॉ रीपर मशीन का उपयोग कर अपने खेत की परली का भूसा बना सकते हैं जिसने शासन द्वारा 130000/- तक का अनुदान है।

राष्ट्रीय पोषण माह अंतर्गत श्रीअन्न और पोषण वाटिका संगोष्ठी का आयोजन

मिलेट्स पोषण वाटिका के साथ जैविक खेती की खूबियों का पढ़ाया गया पाठ

शिवपुरी। जागत गांव हमार

शक्तिशाली महिला संगठन समिति एवं कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के समन्वय में एक दिवसीय संगोष्ठी मिलेट्स (श्रीअन्न) पोषण वाटिका एवं प्राकृतिक खेती विषय पर गत दिवस कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी के परिसर में आयोजित की गई। संगोष्ठी की महत्ता एवं मिलेट्स पोषण वाटिका तथा प्राकृतिक खेती की उपयोगिता एवं प्रसार में भूमिका के लिए ग्रामीण महिलाओं एवं सुपोषण सखियों को जानकारी देते हुए रवि गोयल, शक्तिशाली महिला संगठन समिति शिवपुरी द्वारा विस्तार से बताया। साथ ही संगोष्ठी में दी जाने वाली तकनीकी जानकारी को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसार करने का भी आह्वान किया गया। श्रीअन्न फसलें एवं पोषण वाटिका एवं स्वास्थ्य के बारे में कृषि विज्ञान केन्द्र उज्जैन की वरिष्ठ वैज्ञानिक गृह विज्ञान डॉ. रेखा तिवारी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के द्वारा व्याख्यान दिया गया। विशेषकर महिलाओं में खून की कमी (एनीमिया) और उसके निवारण के उपाय गृह वाटिका के माध्यम से किये जाने के बारे में विस्तार से बतलाया गया। इसी क्रम में श्रद्धा जादौन प्रोग्राम ऑफिसर शक्तिशाली महिला संगठन समिति द्वारा महिलाओं में एनीमिया एवं निवारण के बारे में जानकारी दी एवं समस्याओं का समाधान भी किया।

ग्रामीण महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया

संगोष्ठी में विभिन्न ग्रामीणों से आई ग्रामीण महिलाओं एवं सुपोषण सखियों तथा कृषि महाविद्यालय ग्वालियर से आये ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव के लिए रावे छात्रों सहित सभी को कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी परिसर में डॉ. एमके भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक ने प्रदर्शन इकाइयों जिसमें नवीन स्थापित की जा रही यूनिट ड्रैगन फ्रूट के साथ-साथ फसल संग्रहालय में मिलेट्स फसलें एवं प्राकृतिक खेती इकाई का भ्रमण कराते हुए ग्रामीण महिलाओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। व्याख्यान के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह की महत्ता एवं ग्रामीण महिलाओं की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई।

50 प्रशिक्षणार्थियों की रही मौजूदगी

पोषण वाटिका और स्वास्थ्य विषय पर ग्रामीण महिलाओं को पॉवर पाइंट प्रजेंटेशन के द्वारा डॉ. लक्ष्मी वैज्ञानिक द्वारा समझाया गया। जैव संपदा (बायो फोर्टिफाइड) फसलें एवं प्रजातियों की जानकारी डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह वैज्ञानिक पादप प्रजनन द्वारा दी गई। खाद्य प्रसंस्करण एवं रोजगार के बारे में डॉ. एएल बसेड़िया, वैज्ञानिक कृषि अभियांत्रिकी द्वारा बतलाया गया। रोजगार परख कृषि के लघु उद्योगों के बारे में वायसी रिखाड़ी, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी मत्स्य द्वारा जानकारी दी गई। संगोष्ठी में ग्रामीण महिलाओं को श्रीअन्न प्राकृतिक खेती एवं पोषण वाटिका से संबंधित कृषि साहित्य का वितरण आरती बंसल स्टेनो द्वारा पंजीयन के साथ-साथ किया गया। संगोष्ठी में 50 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता रही।

रीवा में फसलों की उत्पादकता और उत्पादन दोनों में इजाफा

रीवा। जागत गांव हमार

कृषि कॉलेज रीवा के कुठलिया फर्म में संचालित अखिल भारतीय शुष्क अनुसंधान परियोजना के अन्तर्गत एक कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसके मुख्य अतिथि जनार्दन मिश्रा सांसद रीवा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय रीवा डा. एसके त्रिपाठी ने किया और विशिष्ट अतिथि उप संचालक रीवा यूपी बागरी थे। सर्वप्रथम डॉ. एसके त्रिपाठी ने पुष्प गुच्छ देकर सांसद का स्वागत किया। डॉ. आरके तिवारी परियोजना प्रभारी ने परियोजना में हो रही कृषि गतिविधियों पर प्रकाश डाला और कहा कि वर्षा आधारित खेती से कम पानी में अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। इस परियोजना के साथ निकरा के अंतर्गत तीन गांव रायपुर ब्लॉक के रौरा, खीरा और पतोना के कृषक जुड़े हुए हैं।

समन्वित कृषि प्रणाली पर हमें जोर देना चाहिए

सांसद मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि रीवा में फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन दोनों बढ़ा है जो कि सिंचाई का रकबा तीन लाख एकड़ होने के कारण हुआ जिसे अभी अगले आने वाले समय में इसे बढ़ाकर छह लाख करना है। साथ ही कृषकों को कृषि की आधुनिक पद्धति को अपनाकर खेती से लाभ लेना चाहिए। डॉ. त्रिपाठी ने बताया कि खेती से अधिक लाभ लेने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली पर जोर देना चाहिए। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केन्द्र के प्रमुख डॉ. एके पांडेय ने अपना विचार रखा। संगोष्ठी में डॉ. बीएम मौर्या, डॉ. आरपी जोशी, डॉ.वीके सिंह, डॉ. एसएम कुरुमवंशी, डॉ. टीके सिंह, डॉ. राजेश सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार ने कृषकों को संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ. राधा सिंह, डॉ. पीके मिश्रा, डॉ. एके गिरी, डॉ. दिव्या सिंह, डॉ. सुधांशु पांडेय, सतीश सिंह बघेल, सुधीर सिंह,गुल सुप्रिया राय, महोबीया, राजेन्द्र तिवारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पार्षद गंगा प्रसाद यादव के साथ ही साथ श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भी सांसद का स्वागत किया।

कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा स्वच्छता की सेवा अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन

पौधों की पत्तियों और घास को सड़ाकर कंपोस्ट खाद बनाएं किसान

टीकमगढ़। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केंद्र टीकमगढ़ द्वारा स्वच्छता ही सेवा स्वाभाव स्वच्छता एवं संस्कार स्वच्छता पखवाड़ा 15 सितंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक गतिविधियां की जा रही हैं। जिसमें मेगा सफाई अभियान, स्वच्छता की शपथ लेना, स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए दौड़ प्रतियोगिता, मानव श्रृंखला, कृषि कॉलोनी एवं गणेशगंज में रैली निकालना, गंदे स्थान की सफाई, स्वच्छता पर छात्रों द्वारा निबंध प्रतियोगिता एवं संगोष्ठी आदि विभिन्न गतिविधियां प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बीएस किरार, वैज्ञानिक डॉ. आरके प्रजापति, डॉ. एसके सिंह, डॉ. यूएस धाकड़, डॉ. एसके जाटव, डॉ. आईडी सिंह, हसनाथ खान, जयपाल छिगारहा, मनोहर चढार, कृषि स्नातक रावे छात्र एवं कृषकों की सहभागिता अहम है। स्वच्छता पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से

समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता एवं प्रेरित किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि गंदगी से घर, मोहल्ला एवं गांव में बीमारियां पनपती हैं जिससे हमारा इलाज पर काफी पैसा खर्च होता है और गांव मोहल्ला की सुंदरता खत्म होती है। हम स्वच्छता के प्रति अपना स्वभाव और संस्कार में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और वही संस्कार बच्चों को सिखाएं। घरों के कचरा को एक निश्चित स्थान पर डालें और प्लास्टिक की थैली और कांच की सामग्री को अलग-अलग स्थान पर डालें। पौधों की पत्तियों और घास को जलाने की बजाय घूरे में डालकर एवं सड़ाकर कंपोस्ट खाद बनाएं। हैंडपंप और कुएं के आसपास साफ सुथरा रखें जिससे मच्छर न पनपे और परिवार के लोगों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं वायरल बुखार आदि बीमारियों से बचाया जा सके। स्वच्छता की शपथ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में दो घंटे श्रमदान करना चाहिए और मनुष्यों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए काम करना चाहिए। गांव व शहर में स्वच्छता के प्रति प्रत्येक परिवार/व्यक्ति में सकारात्मक सोच-विचार में परिवर्तन लाने का प्रयास जारी रखना चाहिए।

नौकरी छोड़कर ऑनलाइन ट्रेनिंग ली

रील्स देखकर आया ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग का आइडिया: पहले सीजन में कमाए ढाई लाख

सीहोर। जागत गांव हमार

मोबाइल पर रील्स देखना अब आम बात हो गई है। एक रिसर्च के मुताबिक इंडियन यूजर्स हर दिन औसत तीन से चार घंटे स्मार्टफोन पर बिताते हैं। इसमें एक घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर रील्स देखने में गुजरता है। इसमें मनोरंजन के साथ कई बार काम के वीडियोज भी होते हैं। सीहोर जिले के सोंठी गांव के युवा पंकज दांगी को ऐसी ही रील्स देखकर ड्रैगन फ्रूट की खेती का आइडिया आया। ड्रैगन फ्रूट उगाने के लिए पंकज ने इंदौर में नौकरी के साथ ऑनलाइन वीडियोज देखे, ट्रेनिंग ली। 2020 में नौकरी छोड़कर गांव लौटे और खेती को समय देना शुरू किया। 2022 में आधा एकड़ में प्रयोग के तौर पर खेती शुरू की। डेढ़ साल बाद फल आने शुरू हो गए। खेती की लागत करीब 2.5 लाख रुपए पहले सीजन में ही निकल आई। अब 25 साल तक पौधों का सिर्फ मेंटेनेंस करना होगा और हर साल 4 लाख तक की कमाई होगी।

अब जानते हैं पंकज दांगी की किसान बनने की पूरी कहानी

जागत गांव हमार अपने इस अंक में पाठकों को मिलवा रहा है सीहोर जिले के 33 साल के किसान पंकज दांगी से। वे अमेरिकी उपमहाद्वीप में उगने वाले फल ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। पंकज ने 2017 में भोपाल के कॉलेज से बीएससी की है। इसके बाद उनकी नौकरी लग गई और वे इंदौर चले गए। पंकज ने बताया कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी के दौरान हुए स्ट्रेस को कम करने के लिए वे मोबाइल पर रील्स देखते थे। 2018 में उन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती से संबंधित रील देखी। इंट्रेस्ट आने पर कुछ वीडियो और देखे। करीब डेढ़ साल नौकरी की। नौकरी के दौरान जब भी खाली समय मिलता तो वे ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर वीडियो ही देखते थे। 2020 में कोरोना के समय नौकरी छोड़कर गांव आ गए। यहां उनकी 15 एकड़ जमीन है। उस पर पिता हेम सिंह दांगी और बड़े भाई उपेंद्र दांगी पारंपरिक रूप से सोयाबीन-गेहूं सहित अन्य फसलों की खेती करते हैं। पंकज ने एक साल तक बारीकी से अध्ययन किया और 2022 में आधा एकड़ खेत में फार्मिंग शुरू की।

छिंदवाड़ा नर्सरी से मंगवाए पौधे

पंकज ने बताया कि देश में पंजाब, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, ओडिशा सहित अन्य राज्यों में किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे हैं। खेती के लिए सबसे बड़ा चेलैंज था अच्छी किस्म के पौधे लाना। मैंने छिंदवाड़ा नर्सरी से पौधे खरीदे। यहां से 70 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से 250 पौधे मंगाए। इसमें किराया सहित 30 हजार रुपए खर्च हुए। पौधे लगाने के लिए सीमेंट के पोल बनवाए। उन पर रिंग लगवाई। ड्रैगन फ्रूट को सामान्य फसलों की अपेक्षा कम पानी की जरूरत होती है। इसलिए ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था की। पौधे के गड्ढे कराने, खाद, दवा स्प्रे समेत अन्य रखरखाव में पहले साल कुल ढाई लाख रुपए खर्च हुए।

18 महीने में पहली फसल तैयार

ड्रैगन फ्रूट का पौधा करीब 18 महीने बाद फल देने लगता है। इसका फल 250 से 500 ग्राम वजनी होता है। इसमें जून से दिसंबर तक फल लगते हैं। भोपाल मंडी में यह 250 से 350 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकता है। पहले सीजन के फल नवंबर 2023 में आ गए थे। इससे पंकज को करीब 50 हजार रुपए की आय हुई। जून 2024 में पहली बार सभी पौधों पर फल आए। जुलाई से भोपाल मंडी में इनकी बिक्री शुरू कर दी। अब तक करीब 300 किलोग्राम से ज्यादा फल बेच चुके हैं। इस साल 600 किलोग्राम से अधिक पैदावार की उम्मीद है।

रात में खिलता है फूल, 45 दिन में तैयार होता है फल

ड्रैगन फ्रूट का पौधा करीब पांच फीट हाइट के बाद फैलता है। एक पौधे से पांच से सात डालियां बनती हैं। इसका फूल रात में खिलता है। रात में फूल खिलने के कारण इसके परागण यानी फूल से फल बनने में थोड़ी समस्या आती है। सामान्य तौर पर पौधों में तितली और मधुमक्खी के कारण परागण आसानी से हो जाता है। इसके फूल का 100 फीसदी फलीकरण करने और फल का आकार बड़ा रखने के लिए मैन्युअली परागण कराना पड़ता है। रात में जब फूल खिला होता है, उस समय स्टिगमा (फूल का मादा जनन अंग) पर पोलन (पौधों के प्रजनन से जुड़ा होता है) लगाना पड़ता है। इसके लिए ब्रश की मदद से खिले हुए फूल से पोलन को एक प्लेट में निकालते हैं। फिर इसी ब्रश की मदद से पोलन को स्टिगमा पर लगाते हैं। फूल आने के बाद फल पक कर तैयार होने में 45 दिन लगते हैं।

बॉक्स में पैक कर बेचते हैं फल

पंकज का कहना है कि हमारे यहां उपज के बाद उसका मार्केट ढूंढ़ना बड़ा टास्क है। उनका गांव भोपाल से करीब 45किमी दूर है। ऐसे में उन्होंने फलों को बेचने के लिए भोपाल की मंडी का चयन किया। इसके लिए फलों पर ग्रेडिंग के स्टिकर लगाकर कागज के बॉक्स में पैक कर सप्लाई करते हैं। इसके लिए बॉक्स और स्टिकर बनवाया है। एक बॉक्स में 12 फल रखते हैं। पंकज ने बताया कि अभी सिर्फ आधा एकड़ में पौधे लगाए हैं। ऐसे में पूरा काम वे खुद ही देखते हैं। जरूरत पड़ने पर पैकिंग आदि के लिए एक व्यक्ति रखते हैं।

दुनिया में 153 वैरायटी, मध्यप्रदेश के मौसम के लिए अनुकूल

विश्व में ड्रैगन फ्रूट की 153 वैराइटी हैं। सीहोर में पंकज ने सियाम रेड वैरायटी (सी वैरायटी) लगाई है। यह मप्र के मौसम के अनुकूल है। इसे सप्ताह में एक बार पानी देना होता है। इसके लिए ड्रिप सिस्टम लगाया है। इसमें दो प्रकार के फल आते हैं। एक बाहर से लाल और दूसरा पीला व सफेद होता है। लाल वाला फल अंदर से भी लाल होता है। पीला फल अंदर से सफेद होता है। फल की सेल्फ लाइफ 18 से 20 दिन की है। यानी यह पकने के बाद 20 दिन तक खराब नहीं होता है। बेहतर पैदावार के लिए ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं। खाद को प्लांट की जड़ के पास अच्छी तरह से मिट्टी में मिलाते हैं।

एक साल बाद घट जाएगी कॉस्टिंग

पौधे लगाने के बाद पहले दो साल उनकी देखरेख और बड़ा करने में ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। पोल, पौधे सहित अन्य काम में खर्च भी ज्यादा हाता है। इसके बाद हर साल फसल की देखरेख में करीब 50 से 60 हजार रुपए कॉस्टिंग रहेगी। फलों का ट्रांसपोर्टेशन आदि मिलाकर सालाना खर्च एक लाख रहेगा। इसका रिटर्न करीब पांच लाख रुपए सालाना तक रहेगा। पंकज ने बताया कि एक व्यक्ति एक एकड़ तक की खेती अकेले कर सकता है। उसे सिर्फ फलों की पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक साथी की जरूरत रहती है। इससे ज्यादा होने पर देखरेख के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है।

पिता और भाई बोले- हमसे बेहतर है...

इंदौर से नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला लेने पर पंकज को पिता हेम सिंह दांगी और भाई उपेंद्र दांगी के विरोध का सामना करना पड़ा था। दोनों का कहना था तुमने भोपाल में रहकर बीएससी की पढ़ाई की है। इंदौर में नौकरी के दौरान हर महीने 30 हजार रुपए कमाते हो। खेती में सब प्रकृति पर निर्भर है। कई बार गेहूं और सोयाबीन की आई हुई फसल खराब हो चली जाती है। तुम नौकरी में रहोगे तो हर महीने सैलरी मिलेगी। अब करीब दो साल बाद पिता और भाई को पंकज पर गर्व है। दोनों का कहना है कि वह हमसे बेहतर है, उसने पारंपरिक खेती से हटकर खेती है। इस खेती में मौसम की प्रतिकूलता का असर भी नहीं होता है।

नर्सरी बनाई, अब डेढ़ एकड़ में लगाएंगे पौधे

आधा एकड़ में खेती का प्रयोग सफल होने के बाद पंकज दांगी ने इसे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस साल डेढ़ एकड़ खेत में पौधे लगाएंगे। इसके लिए उन्होंने नर्सरी तैयार कर ली है। पोल भी खुद बनवाएंगे। उनका कहना है कि ऐसा करने से कॉस्टिंग कम रहेगी। कोई किसान फसल लगाना चाहता है तो वे नर्सरी से पौधे और ट्रेनिंग भी देने को तैयार हैं। उनका कहना है कि ड्रैगन फ्रूट की खेती की ट्रेनिंग स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च कई शहरों में ट्रेनिंग देती है।

-बीते सप्ताह ग्राम पंचायतों में हुए उप चुनाव में 179 पंच पदो के लिए आए सिर्फ 35 नामांकन,निर्विरोध हुआ निर्वाचन

किसी भी ग्राम पंचायत पंचों के लिए वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी

ग्राम पंचायतों में पंच बनने में नहीं लोगों की रुचि, फिर खाली रह गए 144 पंच के पद

श्योपुर। जागत गांव हमार

ग्राम पंचायतों में पंच बनने के लिए अब लोग कोई रुचि नहीं दिखा रहे है। यही वजह है कि जिले की तीनों जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में 179 पंचों के पद खाली पड़े हुए हैं। विशेष बात यह है कि पंच पदों को भरने के लिए पिछले सप्ताह शासन के द्वारा उप चुनाव कराए गए हैं। इसके बाद भी 144 पंचों के पद खाली रह गए हैं। 179 पंच पदों के लिए सिर्फ 35 ही नामांकन पत्र आए। सभी नामांकन एक-एक होने के कारण 35 पंच पदों पर निर्विरोध ही निर्वाचन हो गया है। किसी भी ग्राम पंचायत पंचों के लिए वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 144 पंचों के पद उप चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी एक बार फिर खाली रह गए हैं। यहां बता दें कि ग्राम पंचायतों के चुनाव के दौरान जिले की ग्राम पंचायतों में 179 पंच पदो के लिए लोगों ने नामांकन ही दाखिल नहीं किए हैं। जिस कारण पंचों के इतने सारे पद खाली रह गए है। प्रदेश के अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों में पंचों के पद खाली रह गए। इसलिए सितंबर माह में ग्राम पंचायतों में खाली रह गए पदों को भरने के लिए फिर से उप चुनाव कराए गए है। जिसके तहत श्योपुर जिले की ग्राम पंचायतों में रिक्त बने 179 पंच पदों को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई।

179 पंच पदो के लिए आए सिर्फ 35 नामांकन

पंच बनने के लिए लोगों में कितनी रूचि है,इसकी बानगी ग्राम पंचायतों के उप चुनाव के दौरान एक बार फिर देखने को मिली है। बताया गया है कि 179 पंच पदों के लिए तीनों जनपदों की ग्राम पंचायतों में सिर्फ 35 पंच पदों के लिए ही नामांकन दाखिल किए गए। सभी नामांकन एक-एक होने के कारण 35 पंचों का निर्वाचन बिना चुनाव ही कराए सम्पन्न हो गए। लेकिन 144 पंच पदो के लिए कोई नामांकन दाखिल नही हुआ जिसकारण 144 पंच पद खाली रह गए हैं।

इस वजह से लोग नहीं ले रहे पंच बनने में दिलचस्पी

पंच बनने में लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। इसके कुछ कारण भी निकल कर सामने आए हैं। पंच पद के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए पंचायत के साथ-साथ बिजली विभाग का नोड्यूज लेना पड़ता है। कई दावेदारों पर बिजली विभाग का बकाया बाकी है ऐसे में उन्हें नोड्यूज नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में पंचों को ज्यादा अधिकार भी नहीं मिले हैं। वह सिर्फ ग्राम सभा में उपस्थित रहकर समस्या ही उठा सकते हैं। सरपंच के पास निर्णय लेने का अधिकार होता है। बैठक में सरपंच और सचिव की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जबकि पंच का इतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से निर्वाचन आयोग ने पंच पद के लिए भी कई नियम बना दिए हैं। पंच पद का नामांकन दाखिल करने में तकरीबन 3000 रुपए खर्च हो जाते हैं। इसके अलावा नोड्यूज करवाने में भी 4 से 5 हजार खर्च हो जाते हैं। इसके बाद गांव में फील्डिंग जमाने में भी रुपए खर्च हो जाते हैं। कुल मिलाकर पंच पद पर खर्चे ज्यादा है और अधिकार कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग रुचि नहीं ले रहे हैं।

सबसे ज्यादा पंचों के पद कराहल की ग्राम पंचायतों में खाली

श्योपुर जिले में तीन जनपद पंचायते आती हैं। जिनमें जनपद पंचायत श्योपुर, विजयपुर और कराहल शामिल हैं। सबसे ज्यादा पंचों के पद जनपद पंचायत कराहल के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में खाली रह गए हैं। बताया गया है कि जनपद पंचायत कराहल की ग्राम पंचायतों में 97 पंचों के पद खाली थे, जिनमें से सिर्फ 16 पंचों के पद ही भर पाए हैं। जबकि 81 पंचों के पद उप चुनाव होने के बाद खाली रह गए हैं। बात जनपद पंचायत श्योपुर की करें तो इसमें 96 ग्राम पंचायत आती है। जिनमें 52 पंचों के पद खाली थे, उप चुनाव के दौरान सिर्फ 16 पंचो के पद ही भर सके हैं। लिहाजा 36 पंचों के पद खाली रह गए है। जबकि जनपद पंचायत विजयपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में 30 पंचो के पद खाली थे। उप चुनाव के दौरान 3 पंचो के पद ही भर पाए है और 27 पंचों के पद एक बार फिर खाली रह गए हैं।

कहां कितने रह गए खाली पंचों के पद

जनपद	रिक्त पद	उप चुनाव में भरे	रिक्त रह गए
श्योपुर	52	16	36
कराहल	97	16	81
विजयपुर	30	03	27
कुल	179	35	144

इधर, ग्राम पंचायत मोरावन में सरपंच की मौत, खाली हुआ सरपंच का पद

जपं कराहल के अधीन आने वाली ग्राम पंचायत मोरावन में सरपंच का पद खाली हो गया है। कारण यह है कि ग्राम पंचायत मोरावन के निर्वाचित सरपंच लालाराम आदिवासी का गत 14 सितंबर को बीमारी के चलते निधन हो गया है। वर्तमान में सरपंच का पद रिक्त होने से ग्राम पंचायत मोरावन में पंचायत की गतिविधियां प्रभावित बनी हुई है। जिस कारण शासन की ग्राम पंचायत से जुडी योजनाओं का क्रियान्वयन अटक गया है। वहीं आमजन के कार्य भी सही तरह से संपादित नहीं हो पा रहे है। इसलिए एसडीएम कराहल बीएस श्रीवास्तव ने एक पत्र जारी करते हुए चार अक्टूबर को ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों की एक बैठक बुलाए जाकर उसमें सरपंच का निर्वाचन उप चुनाव तक कराए जाने के लिए निर्देशित किया है।

इसी माह शुरू होगी 21वीं पशु संगणना

70 कर्मचारी करेंगे सर्वेक्षण

श्योपुर। जागत गांव हमार

पशु की गणना के तहत इस बार पहली बार नस्लवार पशुओं की गणना की जाएगी। जो संभवत: इसी माह में शुरू हो जाएगी। पशुपालन विभाग की ओर से 21वीं राष्ट्रीय पशु गणना 2024 की तैयारी शुरू कर दी गई है। केन्द्र सरकार के पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग की राष्ट्रीय पशुगणना के लिए श्योपुर जिले में 70 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जिनमें 10 सुपरवाइजर और 60 प्रगणक रहेंगे। ये कर्मचारी घर-घर जाकर दस्तक देंगे और पशुओं की गणना करेंगे। इसके अलावा गौशालाओं में मौजूद तथा निराश्रित पशुओं की भी गणना कर ऑनलाइन इन्द्राज करेंगे। बताया गया है कि पशुपालन विभाग की ओर से गणना का कार्य 31 दिसबर तक पूरा करना होगा। बता दें कि इसके पहले वर्ष 2019 में पशु गणना हुई थी। इसके बाद अब यह पशु गणना 2024 में होने जा रही है। यह हर पांच साल में होती है।

16 प्रजातियों की होगी गणना

राष्ट्रीय पशु गणना में पशुओं की 16 प्रजातियों को शामिल किया गया है। हर प्रजाति की अलग-अलग गणना होगी। यानी गोवंश, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़े, मुर्गा-मुर्गी, खच्चर सहित अन्य प्रजातियों की गणना की जाएगी। गणना कार्य के दौरान पशुपालन विभाग की टीम की ड्यूटी लगेगी, ताकि पशुओं से संबंधित डाटा एकत्र करने में विभागीय टीम को ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। राष्ट्रीय पशुगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए 10 सुपरवाइजर और 60 प्रगणक बनाए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये घर-घर जाकर पशुओं की गणना करेंगे। यह पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

डॉ. एसबी दोहरे, उपसंचालक
पशु पालन विभाग,श्योपुर

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)